Regarding CBI inquiry into alleged irregularities in utilisation of funds under PM Poshan Scheme in West Bengal ? laid

श्री खगेन मुर्मु **(**माल्दहा उत्तर**):** पश्चिम बंगाल में पीएम-पोषण के घटिया कार्यान्वयन एवं अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रहने वाली भारत जनसंख्या 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई, जो पीएम-पोषण जैसी कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। पीएम-पोषण योजना देश भर के 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित लगभग 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करती है।

हालाँकि, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, योजना के कार्यान्वयन में गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर पंचायत चुनाव के लिए पीएम**-**पोषण फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है और शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी 'वित्तीय विसंगतियों' के लिए सरकार को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा '100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 16 करोड़ से अधिक मध्याह्न भोजन की 'अति-रिपोर्ट की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन की विशेष ऑडिट के लिए भी कहा, मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के बच्चों को इस अनिश्चित स्थिति से बचाने के लिए सीबीआई जांच सहित गंभीर कार्रवाई की जाए।